Sl. No.	Name of weak State Cooperative Bank
1.	Assam
2.	Chandigarh
3.	Delhi
4.	Manipur
5.	Meghalaya
6.	Tripura
7.	Nagaland
8.	Goa
9.	Pondicherry

फसल बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन

2462. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता से फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए थ्रेशहोल्ड यील्ड निर्धारण के अलग-अलग मानदण्ड रखे हैं तथा विभिन्न राज्यों में क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रशासकीय इकाइयां भिन्न-भिन्न हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री यौनेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा वृहत फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है और प्रीमियम तथा हानियों में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 1:2 के अनुपात में है।

(ख) हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम की राज्य सरकारें और अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र ने अभी तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं । किसी विशेष परिभाषित क्षेत्र की किसी फसल के लिए न्यूनतम निर्धारित उपज" गत पांच वर्षों के लिए उसकी औसत उपज का अस्सी प्रतिशत है । भारतीय साधारण बीमा निगम सिर्फ क्षतिपूर्ति के दावे निर्धारित करता है और उनका भुगतान करता है ।

Agriculture and Horticulture expertise in Pepsi

2463. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the Agriculture or Horticulture expertise Pepsi has;

(b) where has the Pepsi done any work in improving Horticulture;

(c) is not ICAR or any other body able to do what Punjab Agro wants; and

(d) what Agriculture or Horticulture research facilities exist in Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Sir, as per the Punjab Agro-Ttat-Pepsi-cola project document, Pepsico's main research expertise consists of over 250 Scientists with specific applied research responsibilities in Plant genetic, varietal cross-breeding and hybridisation of selected clones and tissue culture.

(b) Pepsi is reported to have done work for improving horticulture in Dallas, Texas, USA and Mexico.

(c) ICAR is already doing research work proposed in Punjab Agro Pepsi project. This will be further strengthened by suitable germ plasm to meet the specific processing requirements of the industry.

(d) Agricultural or Horticultural research facilities existing in Punjab are:

I. Punjab Agrcultural University.

II. Central Potato Research Station, Regional Centre, Jallandhar and

III. All India Coordinated Research Project Centres on:

(i) Tropical fruits at Bhatinda/ Ludhiana.

(ii) Sub-tropical fruits at Abohar.

(iii) Vegetables at Ludhiana, and

(iv) Floriculture at Ludiana

उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2464. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया है, जिसके कारण निर्धन जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया और कि यह रहस्योद्घाटन 19 अक्तूबर, 1986 को ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री ने वाराणसी में किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत सहायता के लिये चुने गए परिवारों में 12 प्रतिशत इस लाभ के योग्य नहीं थे ; और

(ग) सरकार की जानकारी में अन्य क्या-क्या अनियमितताएं आई हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाशत: भारत सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है । हालांकि मात्रा की दृष्टि से प्रगति 1985–86 में लक्ष्यों से अधिक हुई है, राज्य ने 78.14 करोड़ रुपये (आवंटन का 114 प्रतिशत) के सरकारी खर्च से 5.808 लाख लाभार्थियों (लक्ष्य का 107 प्रतिशत) की सहायता की है, किन्तु गुणात्मक आधार पर कुछ कमियां रही हैं । कार्यान्वयन की समस्याओं और अपर्याप्त निष्पादन के बारे में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने अक्तूबर, 1986 में उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दौरान प्रकाश डाला था ।

(ख) जून, 1986 की समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लगभग 12.5 प्रतिशत अपात्र परिवारों को सहायता दी गई थी । किन्तु 9 महीनों (अक्तूबर, 85 से जून 86 तक) की समेकित रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ऐसे परिवारों का प्रतिशत लगभग 9 था ।

(ग) अक्तूबर, 85 से जून, 86 तक की अवधि के लिए समवर्ती मूल्यांकन की 9 महीने की समेकित रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित मुख्य कमियों का पता चलाहै ।

(1) लगभग 10 प्रतिशत परिवार 6400 रुपये की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर सके ।

(2) लगभग 28 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को